

के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने के संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी ल सेतु लिंक) परियोजना प्रदेश त्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल के कायादिश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट में भूमि अवाप्ति के अवार्ड, वन क्लियरेंस एवं अन्य क्लियरेंस के कार्य में गति लाई जाए। उन्होंने इस परियोजना में अब तक

- यमुना जल समझौते की बैठक 20 अप्रैल को, पिलानी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी टास्क फोर्स की बैठक
- भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेषाधिकारियों की होगी नियुक्ति
- ईसरदा पेयजल परियोजना को जून तक किया जाए पूरा

सिंचाई के साथ ही इन जिलों में व्यापित होने वाले उद्योगों को भी विवरण के अनुसार पानी मिल केगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य साथ साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाये।

सच सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में बदलाव कर सहित अन्य सहायताएं प्रदान करने का निर्णय किया। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल साधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल संयोजित विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना की निष्पत्ति पर निष्कर्ष सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिनों में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एवं भूमि आवंटित के दिनों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाये।

मुख्यमंत्री ने संशोधित पीकेसी आराखड़े परीक्षण परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत विवरण एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों

हो चुकी अधिगृहीत भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैडवर्क से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाहकारी नाला हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर समझौत बनी है। इसी क्रम में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रैल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नक़्शे एवं अल्टाइमेट की डिजाइन की तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि परवन वृद्ध बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना की भीतक निर्माण विनियम प्रतिक की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परियोजना में बांध निर्माण कार्य एवं पाइपलाइन विवरण प्रमाण पत्रों को लेकर डिग्री एवं पंप हाउस कार्य में गति लाई जाए। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश अंबासकर सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उनके निवास पर जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति निर्बाध हो : भजनलाल शर्मा

■ 'फील्ड में रहें
अधिकारी, जलापूर्ति
व्यवस्था रखें सुचारू'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गम्भीर की मौसम में पेयजल प्रबंधन एवं सफाई कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को निदेश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्योपजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। उन्होंने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया। उन्होंने जिला स्तरीय समिति के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला स्तरीय समिति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचडी अधिकारियों को फील्ड में रूककर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक का अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गम्भीर की मौसम में पेयजल व्यवस्था

को सुचारु बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप एवं हैडपंप लगाए जायें। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार टैकर्स के जरिए पेयजल परिवहन को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों, नहरों नलकूप एवं हैडपंप के परम्पत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए संश्लिष्ट राज्य एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के

नरौरा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाया। साथ ही, कंट्रोल रूम में दर्ज होने वाली शिक्षाकारों का प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा। उन्होंने बिजली कनेक्शन लेकर नलकूपों में टयूबवैल्वों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने नलकूपों हेतु पंडार में स्पेयर पंप-मोटरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकांशियों को सुझाव देते हुए कहा कि हर ग्राम में पेयजल एवं इससे संबंधित योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पर दो जल मित्र बनाया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका सहयोग लिया जा सके। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य सहायिका मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शिक्षा विभाग के उच्चधिकारी मौजूद रहे।

कम वसूली वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को नोटिस दें : मंजू राजपाल

यपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी मितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु ई जा रही मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज हत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना

■ 'मुख्यमंत्री अवधिपार
ब्याज राहत एकमुश्त
समझौता योजना का
करें व्यापक प्रचार-
प्रसार'



सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बुधवार को नेहरू सहकार भवन में समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया।

लाभांनित हो सका। उहोंने कहा कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। यदि पोर्टल को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए, जिन जिलों में अधिक ऋण राशि बनायी है, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग-अलग रणनीति बनाई जाए।

बैठक में भूमि विकास बैंक के अध्यक्षों द्वारा बताया गया कि योजना की क्रियान्विति के लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न

सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह पाठ्यक्रम चर्चणियों को मौसैज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही कॉल सेंटर को स्थानान्तरण कर सभी पाठ्यव्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों को नियुक्त कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमाण्ड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना के अंगत

नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है। वहीं, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधिपर ऋणों के मामलों में समझावशेष एवं सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गिव अप अभियान में अब तक 17.52 लाख
अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा : गोदारा

- 'खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ होने से जुड़े 19.70 लाख नए लाभार्थी'
- अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में बुधवार को मन्त्रिवालय में जयपुर जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा जिले में गिव अथिफान के तहत अपात्रों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के उपरांत न लाभार्थियों के जोड़ने एवं खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ने हेतु लॉन्ग आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया गया।

मंत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अवधि बढ़ाई जाने से प्रदेश के करोड़ों खाद्य सन्निधि धारकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार वंचितों को उनका हक दिलाने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विभागীয় अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लगातार फ़ील्ड विजिज कर योजनाओं की प्रगति के बारे में फ़ीडबैक लें। जनकल्याण मंत्रालय योजनाओं के बारे में आमजन के

अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएँ ताकि वे समुचित लाभ ले सकें। आमजन एवं जननिष्ठियों से हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित कर प्रभावी क्रियाव्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों को खाद्य सप्लाइ डेडलैन्ड हेतु प्रेरित करने के लिए पाठ वर्ष शुरू किए गए। गिव अप अभियान के तहत आज तक 17.5 लाख खाद्य प्रतियोगिताओं ने स्वतः खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाया है। इस अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 3.24 करोड़ रुपये के राजस्व की बचत प्रत्येक वर्ष होगी। साथ ही संपन्न व्यक्तियों द्वारा खाद्य

समिन्डि छोड़ते से बचे हुए अन्न का
वितरण पात्रों को खाद्य सुरक्षा देने में
इस्तेमाल किया जा सकेगा। गोदार
ने कहा कि एनएफएसए से नाम
हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति
मुख्यमंत्री रमोई गैस समिन्डि योजना
का लाभ भी नहीं ले सकेंगे। इससे
राज्य सरकार को होने वाली बचत
का भी उपयोग वास्तविक हकदारों
के कल्याण हेतु किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा की स्वतः खाद्य समिन्डि
नहीं छोड़ने वाले सक्षम लाभार्थियों
के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक
कार्रवाई की जाए। राशन वितरण
में अनियमिता बरतने वाले राशन
डिलरों पर भी विचारार्थ अधिकारी
उचित कार्रवाई करेंगे।

बैठक में जयपुर ग्रामीण सांसद
रव राजेंद्र सिंह ने कहा कि संपन्न
राज्यों का कर्तव्य है की वह
गरीबों के हक में खाद्य समिन्डि

छोड़ें। उन्होंने कहा की सक्षम लोगों द्वारा छोड़ी गई सब्सिडी गरीब के मुंह का निवाला बनती है। खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़े सभी संपन्न व्यक्तियों को गिव अप अभियान में भाग लेकर इस पुनीत कार्य में पूर्ण सहभागिता निभानी चाहिए।

बैठक में हवा महल विधायक
बालमुकुन्दराय, आदर्श नगर
विधायक रफीक खाँ, चौमू
विधायक शिखा मिल बराला, उपेन
यादव, चंद्र मोहन मीणा, सांगनेर
प्रधान भंवर कंवर, नगर पालिका
चौमू अध्यक्ष विष्णु सैनी, रामपुरा
डाबडी प्रधान हरेदव यादव, शाहपुरा
प्रधान मंजू शर्मा, मनोहरपुर नगर
पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत,
शाहपुरा नगरपालिका चेवरमैन
बंशीधर सैनी सहित विभिन्न प्रतिनिधि
उपस्थित रहे। उन्होंने विभागीय
योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के
संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।
साथ ही बैठक में खाद्य एवं नागरिक
आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन
सहित सुबीर कुमार, जिला कलेक्टर
जयपुर, जितेंद्र कुमार सोनी,
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूतम सागर
सहित सभी विभागीय अधिकारी
मौजूद रहे।

कांग्रेस ने ई.डी. ऑफिस के बाहर धरना दिया

यूपुरा नेशनल हेराल्ड मामले में होक्सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी खिलाफ ईडी की ओर से पेश चार्जशीट देने लेकर कांग्रेस की ओर से देशभर में दर्शन किया गया। इसी सिलसिले में यूपुरा में ज्योति नगर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कांग्रेस सदस्यों ने इस कार्रवाई के विरोध में आगे सड़कों पर उतरने के लिए कार्यकर्ताओं को आवाहन किया।

- राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्ज शीट का विरोध

करते वहाँ आयेकाँठिया का ईमान भाजपा के पैरों में रखा हुआ है, हमारे कुछ नेता इंडी के डर से कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके और जिनके ईमान जिंदा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पंडारे को प्रथममंत्री ने 70 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और 7 दिन बाद ही उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तब उन पर खुब आरोप लगाए थे, लेकिन वह भी भाजपा में जाकर उनकी वाणिग मशीन में थुलकर पाक साफ हो गए।

प्राणीवादी तरीके से सरकार चलाई। हम ऐसे ही कार्यवाही करते तो भाजपा के नेता दिलावर पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से व्यक्ति काम केवल अंगरंग बयानबाजोंजी के समरचना ही हैं और उसे शिक्षा जैसा पवित्रतम काम दिया गया है। हमारी सरकार में ये से व्यक्ति पर कार्यवाही होती तो वो बोलने लगे होते। इनकी बोलने की हिम्मत ही होती।

नेता प्रतिपक्ष टीकराम जुली ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसी का उपयोग कर रही है। इन एजेंसियों में काम

धरने में कांग्रेस विधायक इंदिरा मोघाने ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा दी है, मुझे जान का खतरा है। भाजपा के लोगों ने एक कार्यक्रम के दौरान मुझ पर हमला किया था, हमारी सरकार की कमी रही की भाजपा के लोगों पर हमारी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने को विधायक रफीक खान, सहित मंत्री प्रताप सिंह खारचियावास, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेरा राठौड़, कांग्रेस विधायक अरुण अच्युस आर आर विवाड़ी, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा सहित कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

नेशनल हेराल्ड की संपत्ति खुर्द बुर्द कर देना गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के देशभर में धरने और प्रदर्शन करने की घोषणा पर कहा कि धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है पर उन्हें जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामला में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1937 में नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ था उस समय 5000 शेयर होल्डर थे, यह संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों की है किसी खानदान की जागीर नहीं है। यह कंपनी जब बन रही थी तब सरदार पटेल ने इसके लिए ही धरने धन संग्रह पर सवाल उठाया था कि जिस तरह से लोगों से पैसा लिया जा रहा है यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता ने भी इसके लिए धन इकट्ठा किया था पर जो स्वतंत्रता सेनानियों की प्राप्ति थी वह अब खानदान की प्राप्ति बना दी गई।

■ '50 लाख में हजारों करो फीसदी मां-बेटे की भागी

■ 'भूल केवल वोट बैंक के रही है ममता बेनर्जी'

किसी प्राइवेट बाँड़ी को लोन नहीं दे सकती, जब नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह बेनर्शनल हेराल्ड की कंपनी एमोसिप्ट जनरल लोन नहीं चुका पाई तो कॉर्पोरेट पध्दति करके गांधी परिवार के पास संपत्ति आ जाए इसके लिए यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई गई।

उन्होंने कहा कि इस कंपनी में 38 फीसदी शेयर सोनिया गांधी के और 38 फीसदी शेयर राहुल गांधी के पास रखे गए। शेष शेयर मोतीलाल बोहरा और ऑस्कर फर्नांडीज जैसे लोगों के पास थे। इस कंपनी के नाम 9 करोड़ के इन्वित शेयर इंग्रफोर कर दिए गए केवल 50 लाख रुपए में। जिस कंपनी को यह शेयर दिए गए उस कंपनी में 76 फीसदी की भागीदारी आनी और पुत्र की थी, जिसकी दिल्ली, मुंबई,

की संपत्ति पर कब्जा, 76
री'
नए के दंगाईयों का साथ दे
लखनऊ, भोपाल में हजारों करोड़
की जो प्रॉपर्टी थी। वह भी इस यंग
इंडिया के नाम पर ट्रांसफर हो गई
और 90 करोड़ रुपये जो कांग्रेस ने
दिए वह राइट ऑफ कर दिए गए।
यह एक बड़ा षड्यंत्र था हजारों
करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को हड़पने
का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा
कि इंडी ने मोतीलाल बोरा, पवन
बंसल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी
सबसे बुलाकर पूछा पर किसी के
पास भी जवाब नहीं था। 50 लाख
रुपए में 90 करोड़ का राइट ऑफ
हो जाना और करोड़ों की संपत्ति एक
अनजानी सी अनाम सी कंपनी के
हाथ चले जाना यह गांधी परिवार
मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। नेशनल
हेराल्ड की सरकार द्वारा संपत्ति दी
गई थी उसे खुद बुद करने का यह
भ्रष्टाचार का खुला आचरण है।

बजट घोषणाओं का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : दिलावर



पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया।

जयपुर। पंचायती राज संजी मदन दिलावर नेवें २०५१-२५ एखें वारं २०२५-२६ को बिगाराणी बजट घोषणाओं के कायोरी कौ शीर समबद्ध क्रियाचन सुनिहैं करणे के निर्देश दिया है। उन्हीं बजट घोषणाओं के काय में हो रही देरी परत सारागी व्यक्त की और अधिकारियों को नमराये से घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देश किया।

दिलवार आज बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभागीय वर्ष वित्तीय वर्ष २०२४-२५ एवं वर्ष २०२५-२६ के बजट घोषणाओं के लम्बित प्रकरणों, कार्यो के क्रियाचन एवं अधिकारियों के राशि विभक्त के संबंध में

आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता व
रहे तथा उन्होंने अधिकारियों को निदेश दे
हुए कहा कि बजट घोषणाओं
क्रियान्वयन के संबंध में कार्यों को पूर्ण का
के लिए समय सीमा निर्धारित करते हु
कार्यवाही प्रारम्भ करें। उन्होंने स्वाभि
योजना की प्रगति पर सतोष व्यक्त कि
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की
बजट घोषणाओं के लंबित प्रकरणों
त्वरित क्रियान्वयन के लिए अधिकारि
को निदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों द्वा
कि गए दौरो और रात्रि विश्राम व
विस्तार से जानकारी लाई। उन्होंने निरीक्ष
के दौरान प्राप्त पंचावली में मंदीगी प

जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों कायवाही करके ने निर्देश दिए। इससे जटिलता बर्कत एवम् भू संरक्षण विभाग और फाउंडेशन फॉर इकोलाजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) के स वनस्पति सौड बैंक के संबंध में एमओ पर भी हस्ताक्षर किए गए। अंत में बैठक में डॉ. गोतागरा शासन संविधान आयुक्त जेयराजी रायने ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुहम्मद जैव निदेशक जल ग्रहण विकास एवं संरक्षण विभाग, सोलौनी खेपवन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व अन्य विभागीय अधिकारी ग उपस्थित थे।